

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 18/2013/एलआर

1. शांतिलाल पिता गोपीलाल धोबी
 2. कन्हैयालाल पिता गोपीलाल धोबी
 3. मु. कस्तुरी बेवा गोपीलाल धोबी
- तीनो निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. बबूलाल पिता सोहनलाल पूर्बिया (बालोटिया)
निवासी गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. राज्य जरिये कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार, गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड जरिये डिवीजन मैनेजर भारत
पेट्रोलियम राणा प्रतापनगर स्टेशन के पास मादडी इण्डस्ट्रीज
एरिया रोड उदयपुर।
5. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई 10—ए पंचवटी उदयपुर
6. स्वपंच ग्राम पंचायत गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय व आदेश जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
दिनांक 02.02.2012 प्रकरण सं. राजस्व/कृ.भूरू.
/पेट्रोल/11/11/13

- उपस्थित –
1. श्री रमेश चन्द्र दशोरा – अभिभाषक अपीलान्टस
 2. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-1
 3. श्री मुकुट बिहारी दाधीच – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट- 5
 4. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि ग्राम गंगारार तहसील गंगारार जिला चित्तौड़गढ़ में रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बाबुलाल ने पेट्रोल पम्प हेतु आ.न. 2569/5025 रकबा 0.25 है० में से 675 वर्गमीटर आराजी नम्बर 2570/4592 रकबा 0.21 है० में से 850 वर्गमीटर, आ.न. 2570 मी. रकबा 0.03 है० में से 250 वर्ग मीटर, आ.न. 2571/4599 रकबा 0.05 है० में से 250 वर्गमीटर कुल कितना 4 रकबा 2025 वर्गमीटर भूमि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन करने का आदेश अवैध है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

2. अपीलान्त की खातेदारी की आराजीयात रेस्पोजेन्ट संख्या 1 बाबुलाल की भू-रूपान्तरण कृषि भूमि आपस में मिली हुई होकर रेस्पोजेन्ट सं. 1 बाबुलाल की पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूमि का अपीलान्त उत्तरी दिशा का पडौसी है। अपीलान्त की आराजी नम्बर 1388 रकबा 19 बिस्वा आराजी नम्बर 1389 रकबा 11 बिस्वा कुल 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि साबित बन्दोबस्त में खातेदारी में चली आ रही थी और नवीन बन्दोबस्ती रेकार्ड में निम्न प्रकार परिवर्तन हुआ है। नवीन खसरा नम्बर 2572 रकबा 0.24 है० ही दर्ज है जबकि भूमि का क्षेत्रफल 0.32 है० दर्ज होना चाहिये था उक्त भूमि को हाल सेटलमेन्ट के दौरान रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के खाते में जोड़ दी गई है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के भू-रूपान्तरण की गई भूमि का साबिक बन्दोबस्त की खसरा नम्बर 1387 होकर रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा दर्ज रेकार्ड था, लेकिन नवीन बन्दोबस्त रेकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 2567 रकबा 0.46 है० आराजी नम्बर 2570 रकबा 0.24 है० आराजी नम्बर 2571 रकबा 0.18 है० दर्ज कर दिया है। कुल रकबा रेस्पोजेन्ट का 0.68 है० दर्ज नवीन रेकार्ड में हाल सेटलमेन्ट में दर्ज हो गया है। इस प्रकार अपीलान्त का 0.28 है० भूमि को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की आराजी नम्बर 2567 रकबा 0.46 है० 2570 रकबा 0.24 है०, खसरा नम्बर 2571 रकबा 0.18 है० कुल रकबा 0.88 है० हो गया

है। रेस्पोजेन्ट का इन तीनों आराजीयात में गणना करने पर मात्र 0.70 है० भूमि ही बनती है। भू-प्रबन्ध विभाग ने रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के रकबे में बढ़ोतरी करते हुए भू-रूपान्तरित किये जाने वाले नम्बरान नवीन नम्बर कायम किये हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट की ओर से इन्द्राज दुरस्ती की वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है और रेस्पोजेन्ट ने उक्त तथ्यों को छिपाकर अपीलान्ट की आराजीयात में से 0.08 है० भूमि का पेट्रोल पम्प हेतु भू-रूपान्तरण आदेश गुप्त रूप से पारित करवा लिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोजेन्ट का प्रथम आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ उसमें तथ्यों को छिपाकर बिना दस्तावेज प्रस्तुत किये ही आवेदन पेश किया गया जिस पर कोई तारीख आवेदन प्रस्तुत करने की ही अंकित नहीं थी उसके बाद दिनांक 22/06/2011 को आवेदन प्रस्तुत हुआ जिसमें जिला कलेक्टर ने पुनः आवेदन पत्र रेस्पोजेन्ट का लौटाया है और रेस्पोजेन्ट से एतराज पूर्ति करने के निर्देश दिये हैं जिसमें भू-रूपान्तरण कार्यवाही की पत्रावली में स्वयं पटवारी हल्का ने लाल स्याही से नक्शे में भू-रूपान्तरण किये जाने से पूर्व तरमीम कर नक्शा रेस्पोजेन्ट को दिया तथा ग्राम पंचायत से पत्रावली में सीधी अनापत्ति प्रस्तुत कर दी जबकि ग्राम पंचायत से अनापत्ति जिला कलेक्टर को मंगवाई जानी चाहिये थी। ग्राम पंचायत की दिनांक 05/07/2011 को कोई विधिवत कोरम ही नहीं बनी थी। ग्राम पंचायत ने सुनवाई का अवसर दिये बगैर पडोसियों से व सार्वजनिक रूप से की गई आपत्तियों पर विचार किये बगैर ही अवैध रूप से अनापत्ति जारी की गई है जिससे उक्त रूपान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कोई अनापत्ति पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुई है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पूर्व दिश में नेशनल हाईवे 79 विद्यमान है जो फोरलेन से विस्तार होकर सिक्सलेन के निर्माण की घोषणा हो चुकी है और भारतीय रोड (इण्डियन रोड काग्रेस) के नियमों के तहत सिक्सलेन के बीच से कितनी दूरी रेस्पोजेन्ट

संख्या 1 को छोड़नी है का मापदण्ड तय नहीं किया गया है मात्र इण्डियन रोड कांग्रेस के फोरलेन के तहत भू-रूपान्तरण आदेश किये जाने योग्य है। जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 21/7/2011 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र लिखकर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तथा परियोजना निदेशक उदयपुर द्वारा अनापत्ति पत्र हेतु जयपुर कार्यालय को लिखा लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर से अनापत्ति पत्र प्राप्त हुए बगैर ही पेट्रोल पम्प हेतु भू-रूपान्तरण किये जाने में जिला कलेक्टर ने कानूनी भूल की है जिससे भू-रूपान्तरण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रूपान्तरित की जाने वाली भूमि आबादी से घिरी हुई होकर चारों तरफ आबादी बसी हुई है। घनी आबादी के बीच पेट्रोल पम्प की स्थापना की जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा आदेश दिनांक 02/02/2012 को किया जिसकी जानकारी अपीलान्टस को नहीं थी। अपीलान्ट को जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील के साथ धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि विवादग्रस्त भूमि पर एक पेट्रोल पम्प चल रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट का पड़ोसी है। अपीलान्ट की जमीन में 0.80 है० भूमि पैमाईश के दौरान कम हो गई इसको लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सिविल न्यायालय में वाद चल रहा है। उपखण्ड अधिकारी गंगरार के न्यायालय में प्रकरण 85/2015 इस प्रकरण में दर्ज है जिसमें पिछली तारीख पेशी 18/01/2018 तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई है। जहां तक सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण का सवाल है रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि नारायण पिता केला तेली, भाई राजेन्द्र कुमार के पावर ऑफ अटॉर्नी से जो कि अपंजीकृत है, से बाबूलाल द्वारा दिनांक 19/08/2003 को विक्रय दस्तावेज को उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 22/08/2003 को पंजीबद्ध

हुआ जिसकी अपील अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीष-प्रथम चित्तौडगढ के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। उल्लेखित दावा खारीज हो जाने के फलस्वरूप अपील संख्या 243/2011 प्रस्तुत की गई जो लम्बित है। जिला कलेक्टर द्वारा बिना सुनवाई करे तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत तथ्यो पर आधारित रिपोर्ट के आधार पर पेट्रोल पम्प हेतु भू-रूपान्तरण किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय उच्चमार्ग अधिकरण से भी रिपोर्ट नहीं ली गई है। इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा किया गया भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 11/11/2013 विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. दौराने बहस वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं 5 ने बयान किया कि अपीलान्त पेट्रोल पम्प हेतु भूमि रूपान्तरित कर देने से किस प्रकार प्रभावित है इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इसकी ताईद में किसी प्रकार का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे पूर्व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जो विवादित आराजी का खातेदार कृषक है, ने समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भूमि रूपान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी जिला कलेक्टर द्वारा जांच के पश्चात् पूर्ण संतुष्टि कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। भूमि की खातेदार अलोल बाई, पूर्णिमा वगैरह है जिन्हे इंतकाल संख्या 2705 दिनांक 07/12/2009 के द्वारा खातेदारी मिली है। इसी प्रकार इंतकाल संख्या 2700 दिनांक 07/12/2009 के द्वारा अन्य भूमि खसरा नम्बर 2539, 2569 तथा 2571 की खातेदारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बख्शीषनामे के माध्यम से इंतकाल संख्या 2714 दिनांक 07/12/2009 से खातेदारी प्राप्त हुई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीष के निर्णय के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में की गई है जिसका अनवान नारायण वगैरह बनाम केला तेली वगैरह है जिसमें शांतिदेवी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में वाद लम्बित होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा किसी भी प्रकार की तिथि का उल्लेख नहीं है। राजस्व

वाद 2013 में प्रस्तुत हुआ है जबकि भूमि रूपान्तरण उससे पूर्व ही हो चुका है। उनके द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालय की आदेशिका की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार दिनांक 30/08/2013 को शांतिलाल अपीलान्त ने वाद विद्धो कर दिया। ऐसी सूरत में यह कहना कि तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, सही नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

6. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक ने बयान किया कि जिला कलेक्टर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि रूपान्तरण किया गया है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्तस खारीज की जावे।

7. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से मौका एवं रिकार्ड के अनुसार रिपोर्ट मंगवाते हुए सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि रूपान्तरण किया गया है। अपीलार्थी स्वयं के द्वारा दिनांक 30/08/2013 को अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में वाद विद्धो कर लिया गया है तथा सिविल वाद भी खारीज हो चुका है जिसकी माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। जिसमें रेस्पोंडेन्ट वगैरह पार्टी नहीं है तथा प्रकरण में नोटिस जारी हुए हैं किसी प्रकार का अन्यथा आदेश भी रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। जिला कलेक्टर द्वारा खातेदार की खातेदारी भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। ऐसी सूरत में अपील अपीलान्तस खारीज की जाती है एवं जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/कृ.भूरू./पेट्रोल/11/11/13 का आदेश दिनांक 02/02/2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़